अपने उस पुराने निर्णय को पुष्ट किया है। कर्नाटक की सरकार, जहां से स्वयं मिसेज़ मारग्रेट आल्वा हैं, कर्नाटक की सरकार को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता, आप जिस मर्जी के लिए आरक्षण करिए लेकिन कुल मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि इस 50 फीसदी की सीमा में एस० सी०/एस० टी० का आरक्षण साढ़े बाइस प्रतिशत है, उसमें भी एस० टी० का आरक्षण साढ़े सात प्रतिशत है तथा एस० सी० का आरक्षण केवल 15 प्रतिशत है। अगर क्रिश्चियन दलित के नाम पर एक और वर्ग को इसमें जोड़ा जाता है तो उसी 15 प्रतिशत के हिसेदार वे होंगे जो 15 प्रतिशत आलरेडी हरिजनों को मिला हुआ है। इससे पहले भी जब एक्स सर्विसमेज के लिए आरक्षण रखा गया, विक्लांगों के लिए आरक्षण रखा गया तो उनमें जो एस० सी० थे उनको इस 15 प्रतिशत के अगेंस्ट जोड़ दिया गया। अब अगर एक अलग वर्ग और वह वर्ग भी कौन सा, जो इन हिन्दू हरिजनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पढ़ा-लिखा है, कान्वेंट एजुकेटिड है, अगर उनको इस 15 प्रतिशत में जोड़ा गया तो वह हिस्सा किसका मारेगा उस 15 प्रतिशत का, जिनको पहले ही अपनी आबादी से कम हिस्सा मिला हुआ है। इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह मांग हरिजनों को मिले हुए हिस्से में से और ज्यादा उनके हिस्सा कम करने की मांग है, आलरेडी हरिजनों का जो उपेक्षित वर्ग है, उन पर अन्याय करने की मांग है। इसलिए ये दो प्रमुख कारण हैं, कारण तो और भी हैं, लेकिन ये दो प्रमुख कारण हैं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): इसमें कोई डिबेट नहीं हो रही है, समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से मेरा दल आरक्षण की इस मांग का विरोध करता है और इस बात को मैं दर्ज़ कराना चाहती हूं।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Mr. Nilotpal Basu, you have not sought permission. If you are allowed to speak, then I will also speak. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष जी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): श्रीमती सरला माहेश्वरी जी, आपका एसोसिएशन मैंने लिख दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: इसमें अलग तरह के विचार भी आए हैं और एक बहसनुमा रूप दे दिया गया है इसको। इसलिए पहले तो मेरा ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) इसलिए मैंने उनको रोक दिया है। सुषमा जी को इसलिए रोका है कि इसमें कोई डिबेट नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जब पूरी बहस को यहां रूपांतरित किया जा चुका है तब मैं समझती हूं...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): दो स्पेशल मेंशन और हैं। अगर वह खत्म हो जाएंगे तो ढाई बजे दूसरा विषय ले लेंगे। राघवजी बहुत इंतजार कर रहे हैं। आपका एसोसिएशन में लिखा देता हूं विद मि० जॉय एंड मि० वायालार रवि ने भी कहा है। आपका भी एसोसिएशन है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): हमारे संविधान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा देश एक धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र होने के नाते राज धर्म के नाम पर अपने आर्थिक लाभों के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह हमारे संविधान निर्माताओं की स्पष्ट समझ थी और इसी स्पष्ट समझ के साथ हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि हमारे संविधान में जो दलित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं सिर्फ इस कारण से उन्होंने दूसरा धर्म ले लिया है। ...(**व्यवधान**)... इस कारण राष्ट्र का यह अधिकार नहीं बनता कि वह उनकी जायज मांगों की उपेक्षा करें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I also want to associate myself with this Special Mention. I want to say that untouchability was not the criterion for reservation. It is a wrong impression because untouchability is a crime in India today. So, it cannot be a criterion for reservation. Normally, Sir, these are the reservations meant for those Indians who are socially and economically backward and if they change their religion, they do not cease to be Indians. They continue to be Indians. So, it cannot be a bar. So, I fully endorse the views of my hon. friend.

Acute Shortage of Power in Karnataka

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. House the problem of acute shortage of power in Karnataka. The power crisis in Kernataka is so acute that

if timely action is not taken by the Centre, Bangalore will become another Calcutta of 1970 and the industies will start going away from Karnataka. Karnataka has never faced such a crisis in the past. The Karnataka Government has almost given up the idea of taking any action. It has no will power to solve the problem. The joke in Karnataka is: "When will the power be there?" The cities and towns are almost in darkness. The industrialists are crying and the State/Government is just watching. The small-scale industries are almost closing down and have no capacity to go in for captive power. People are at a loss to understand why all of a sudden this crisis has arisen. On earlier occasions also, there used to be a failure of monsoon, but such a situation has never arisen in Karnataka. Last year, during the same season, there was no power cut or no power shortage. The Government of India cannot be a silent spectator to the situation. The Central Government should come to the rescue of the people of Karnataka by allotting additional power from the Central Grid to meet the crisis and save Karnataka. Bangalore has been considered as a Silicon Valley of Asia and poised to become the world capital in electronics. The State Government does not seem to be keen to face the situation. I appeal to the Government of India to take urgent steps to provide 500 mega watts of additinal power to Karnataka immediately. I also urge upon the Government of India to clear all the pending power projects in Karnataka and expedite the work. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri B.K. Hariprasad. Do you want to associate yourself with it?

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Yes, Sir, I am also associating myself with this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Your association is on record.

Unprecedented Power Crisis in Madhya Pradesh

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) श्री राघवजी, जल्दी खत्म करिए। बहुत टाइम हो गया है।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने से अभूतपूर्व बिजली संकट है। कारखाने लगभग बंद पड़े हैं। 25 प्रतिशत यूनिटों में उत्पादन नहीं हो रहा है। छोटे छोटे उद्यमियों को अपना काम बंद करना पड़ा है। आटा चक्कियां, वेल्डिंग मशीनें सब बंद हैं, पीने के पानी की व्यवस्था खत्म हो चुकी है क्योंकि वह भी बिजली पर आधारित है। अस्पतालों में आपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर बिजली नहीं मिल पा रही है। सरकार यह कहती है कि हम सिंचाई के लिए बिजली दे रहे है इसलिए शहरों में बिजली बंद है। लेकिन गांवों की हालत शहरों से भी बदतर है। पिछले एक महीने से सिंचाई के लिए गांवों में बिजली नहीं जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जहां दो दो महीने तक बिजली नहीं पहुंची है। जहां बिजली पहुंची है वहां दिन में दो घंटे भी बिजली नहीं रहती है। पलेवा नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से बोनी नहीं हो पा रही है और इसके कारण से खेती भी प्रभावित हो रही है और इस तरह से नगरों और गांवों में दोनों जगह बिजली का बहुत बड़ा संकट हो गया है...(समय की घंटी) में दो मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): नहीं, दो मिनट नहीं। आपकी चीज रिकार्ड पर आ गयी है। इतना ही काफी है।

श्री राघवजी: इसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री ने भी तीन दिन के लिए धरना दिया है। कांग्रेस के एक मुख्य मंत्री ने एक आरोप लगाया है कि यह सब कुप्रबंध के कारण है और जानबूझकर जो 22 परियोजनाएं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। उनको वैलिड ठहराने के लिए उनका काज मजबूत करने के लिए वर्तमान व्यवस्था अस्त व्यस्त की जा रही है। इसके कारण बिजली संकट पैदा हुआ है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र शासन जल्दी से जल्दी इसमें हस्तक्षेप करें ताकि मध्य प्रदेश की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now, we take up the Private members' business, but before we do that, I would request